RAJYA SABHA

Monday, the 8th December, 1969/*the 17th Agrahayana* 1891 (Saka)

The Housa net at eleven of the clock, MR. CHVIRMAN' in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलों म तोड़फोड़ के बारे में वांचू समिति का प्रतिवेदन

*442. डा० भाई महावीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वांचू समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा है कि रेलों में तोड़फोड़ के मामलों पर राज्यों का पुलिस प्रशासन पर्याप्त ध्यान नहीं देता है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1958-59 से 1968-69 तक की अवधि में तोड़फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाओं के 27 मामलों में से पुलिस ने केवल 23 मामले दर्ज किये और उनमें से भी 7 मामलों में अपराधियों का पता नहीं लग सका; एक मामले में अभी छानबीन जारी है और शेष पांच में से तीन में अभियुक्त बरी हो गये और केवल एक मामले में सजा हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

t [WANCHOO COMMITTEE ON SABOTAGE IN TIE RAILWAYS

*442. DR. BHAI MAHAVIR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Wanchoo Comn ittee in its second report • have stated tha the Police administra tion in the States do not pay adequate attention to the cases of sabotage in the Railways;

(b) whether it is a fact that out of the 27 case- of accidents due to sabotage during the period from 1958-59 to 19'>8-69, the Police regis tered 13 cases inly and in seven cases out of them the culprits could not be traced; one case is still under in- ! vestigation and in three out of the I remaining five cases the accused have been acquitted and only in one case punishment was awarded; and

(c) if so, what is the reaction of Government in the matter?]

विधि तथा समाज कल्याण और रेल मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तोड़फोड़ से रेलवे लाइन की हिफाजत करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । वांचू समिति के विचार/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को आगे उपयुक्त हिदायतें जारी करने के प्रश्न पर गृह मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

t[THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI P. GOVIND A MENON) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

j(c) Responsibility for the protection of railway track against sabotage, rests with the State Governments. In the light of the observations/recommendations of the Wanchoo Committee, the question of issuing further suitable instructions to (he State Governments is under consideration in consultaiion with the Ministry of Home Affairs.]

डा० भाई महावीर : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इतने गम्भीर प्रश्न पर खाली एक टेकनिकल उत्तर देकर किस प्रकार से संतोष कर लेती है । रेलवे लाइनों की तोड़फोड़ का मामला राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, यह कहा गया । क्या मंत्री महोदय कृपा करके यह बतलायेंगे कि क्या रेलवे प्रशासन और गृह मंत्रालय के मध्य इस प्रश्न पर कुछ मतभेद हैं और दोनों सहमत नहीं हो पा रहे कि पुलिस को इस तरह की तोड़फोड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाये क्योंकि तर्क यह गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, ऐसा कहा गया है, कि केवल

t[ ] English translation.

एक प्रतिशत दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण होती है इसलिये इतना थोड़ा जिसका महत्व है उसके लिये हम विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या मंत्री महोदय मुझे यह बतायेंगे कि क्या आपने उनके इस तर्क को स्वीकार किया, या उनको यह बताया कि एक प्रतिशत घटनाओं के बावजूद, 30 प्रतिशत के करीब जो सम्पत्ति की हानि होती है, वह इस तोड़फोड़ की घटनाओं के कारण होती है। इसलिये इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था अवश्य की जाये इस संबध में गृह मंत्रालय और रेलवे प्रशासन के बीच क्या फैसला हुआ है?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : अभी फैसला कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला जल्दी तय हो। यह बड़ा गम्भीर मसला है, इसमें बगैर राज्य सरकारों की मदद के रेलवे प्रशासन खुद कुछ विशेष नहीं कर सकता।

डा० भाई महावीर : मंत्री महोदय ने फिर वही जवाब दिया कि बड़ा गम्भीर मसला है इसलिये हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। यह जो समाचार छपा है यह 12 सितम्बर के दैनिक पत्र का है, वान्चू कमेटी की रिपोर्ट इसके पहले की होगी, और अब हम दिसम्बर के मध्य के क़रीब आ गये हैं। इन तीन महीनों में अगर सरकार के दो विभागों में इस संबंध में फैसला नही हो पा रहा और परिणाम यह है, जैसा आपने स्वीकार किया, 27 तोड़फोड़ के मामलों में से केवल एक में दंड दिया जा रुका है। यदि देश की जनता, देश के रेल यात्रियों की सुरक्षा का प्रबन्ध यही है तो रेल पर उनके बैठने से पहले हम यह कह दें कि वह कम्पलसरी इन्शोरेन्स करा के जायें क्योंकि सरकार किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले नहीं सकती, तीन महीने से आप अपने सरकारी महकमों में फैसला नहीं कर पाये, तो आगे कितनी देर इसमें लगेगी, आगे कब इसकी व्यवस्था करेंगे। तोड़फोड़ कई गुना हत्या के बराबर हैं। एक आदमी कत्ल करता है उसे फांसी का दंड दिया जाता है, जो व्यक्ति सैकड़ों की हत्या करते हैं उनके बारे में आप अभी बातचीत ही कर रहे हैं और कहते हैं बड़ा गम्भीर मसला है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यह हमारी समझ में नहीं आया, कृपा करके मंत्री महोदय इसका समाधान करें।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि रेलवे प्रशासन स्वयं इसमें कुछ खास नहीं कर सकता है, सिर्फ राज्य सरकारों के सामने इस चीज की अहमियत को ला सकता है और गृह मंत्रालय के माध्यम से ही हम राज्य सरकारों से कह सकते हैं। सन् 1967 में हमारे रेलवे विभाग के डाइरेक्टर, रेलवे सेफ्टी और जौइन्ट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री दोनों मिले और दोनों ने विचार विनिमय किया। उसके बाद इस साल जुलाई में भी हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने गृह मंत्रालय को लिखा। आई० जीज० को भी हम लिखते हैं और सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि कायदे कानून जिस तरीके से हैं, उसमें रेल मंत्रालय खुद इसमें अधिक कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अपने गृह मंत्रालय को और प्रान्तीय सरकारों को उसकी गम्भीरता बता सके और इसके लिये जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं।

DR. BHAI MAHAVIR : I appeal to you, Sir, just to impress upon the Government, to consider if this type of an answer is in keeping with what we profess for the welfare of the common people. The technical answer is that the Railway Safety Officer met so and so, the Secretary wrote to such and such Department. And there it ends, and months and months pass and the people, the innocent travellers, are being left to the mercies of the saboteurs in this country. If the answer is going to be given only in a technical manner that this Ministry has nothing to do and that Ministry has to do. I would request you. Sir, to consider this that our question is addressed to the Government and it is the duty of this

Government to take the necessary deci- i sions and put a stop to this type of nefarious acth ties indulged in by the saboteurs.

SHRI A. D. MANI : Sir, as the hon. Minister has ;iid that the Railways have to look 1} the State Administrations in this regard, may I ask him whether he kn;w of the fact that railways were na: onal property and he could seek thi co-operation of the States to allow the Central Intelligence Bureau to investigate cases of sabotage, and initiate acion, as is being done by the Company Law Enforcement Directorate in the i ase of company affairs ?

SHRI RCHANLAL CHATUR-VEDI : This s a matter for action; it is a good suggestion.

SHRI GULAM NABI UNTOO : Sir, what are the percentages of the accidents whic 1 are caused by sabotage, and those whi;h are caused by natural causes or negligence of the employees, and whether t IC Government has been able to locate from the nature of the sabotage, whe'her it is exclusively the work of thos'" who are inside the country, or is there some foreign hand also in it ?

SHRI P. C DV7NDA MENON : Sir, regarding the aercentages of the accidents, which have been the result of sabotage, and others, which have been due to negligence on the part of the railway peopl;, I would like to have separate notice, in which c^se I would be abJe to gi e the information.

SHRI M. \ BHARGAVA : May I know, Sir, *i* om the hon. Railway Minister wha prevents him from utilising the Raih/ay Protection Force in a much more elective manner for preventing such sar otage activities ? And if he finds that the powers given to the R.P.F. are n >t adequate enough, what steps he proposes to take to see that adequate powers are given to the R.P.F. to meet the situation created by the activi ies of the saboteurs?

SHRI P. C OVINDA MENON : Sir, even when I answer this question, again the comment that it is a technical answer may be put forward. Sir, law and order being a State subject even the Railway Protection Force cannot prosecute persons in the State courts, and it this situation should be changed, the Constitution will have to be changed.

SHRI M. P. BHARGAVA : Is the Constitution more sacrosanct, or the safety of the people ?

SHRI P. GOVINDA MENON : Now if we proceed on the assumption that the State Governments will not be prepared to prosecute the offenders, then these difficulties arise. The question is whether the Constitution is more sacrosanct than ihe safety of the people.

If the safety of the people requires that the Constitution should be amended I am sure this House will be agreeable to an amendment of the Constitution. Now we have not yet felt that that situation has been reached.

SHRI AKBAR ALI KHAN : Sir, I fully appreciate the answer of the hon. Minister that this is a matter in which he has to proceed through the Home Ministry but what the House is anxious to know is in view of ihe importance of this problem whether the Railway authorities, the Home Ministry and the State authorities have met and chalked out any plan for that or whether this is still a matter of correspondence and negotiations.

SHRI P. GOVINDA MENON : There has been no conference of representatives of State Governments and representatives of the Home and Railway Ministries in that sense but there have been letters and requests addressed to the States Administrations on this question.

श्री गनेशी लाल चौधरी : माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स की मर्सी के ऊपर है। जहां तक रेलवे में प्रोटेक्शन की बात है और मनुष्यों की जिन्दगी तथा प्रोटेक्शन की बात है, तो यह चीज होम मिनिस्ट्री और स्टेट्स गवर्नमेंट के मर्सी के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती है। क्या मंत्री जी कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे रेलवे में यात्रियों की जान व माल की हिफाजत हो सके।

SHRI P. GOVINDA MENON : It is not correct to say that we are at the mercy of the Home Ministry or of the

State Governments. What the Wanchoo Committee said in para 260 of the Report is this :

> We feel that cases of wilful tempering with track do not receive from the State police and the other authorities concerned with law and order the attention they deserve."

Now, Sir, the Wanchoo Committee has pointed out that the attention should be on the part of the State Administrations and the State Administrations will be requested to advert to this matter and this finding of the Wanchoo Committee will be communicated to the State Administrations.

SHRI P. C. MITRA : From the reply of the hon. Minister it appears that certain State Governments have not given you full co-operation in this matter. May I know from the Railway Minister which are the States which have not offered co-operation in stopping this sabotage ?

SHRI ROHANLAL CHATUR-VEDI : It does not concern any particular State; it is a general law and order problem. After all, these incidents cover almost all the States, about 10 States.

SHRI P. C. MITRA : Does it mean that no State has offered any co-operation in stopping sabotage?

SHRI P. GOVINDA MENON : The observation of the Wanchoo Committee is based upon 28 accidents which took place in different States as follows : Bihar—8, Assam—4, Andhra Pradesh—3, West Bengal—3, Mysore—3, Uttar Pradesh—2, Maharashtra—1, Gujarat—1, Madhya Pradesh—1 and Rajasthan—1. Therefore it is not as if any particular State did not do the proper thing in this matter. The Wanchoo Committee has said that the State Administrations should bestow more attention. The Wanchoo Committee has not come to the conclusion that the State Administrations are deliberately ignoring their responsibilities. Their finding, as I read out, is that they feel that sufficient attention is not being wed on this matter and we have drawn the attention of the State Administrations to this aspect and there is no reason to think that the State Governments are not careful after this matter has been brought to their notice.

SARDAR D. K. JADHAV: May I know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that most of the personnel of uie police transferred to the Railway Department have either incurred the displeasure of the State Governments or are most in-efficient and that being the situation how can there' be any safety and how can proper action be taken in such matters?

SHRI P. GOVINDA MENON : I shall examine whether this information is correct.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं मंत्री जी से एक नन्हा सा और एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जून के महीने में जखनियां स्टेशन में एक एक्सीडेंट हो गया था जिस के बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को दोष देती है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को दोष देती है। सभापति जी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि यह एक अद्वितीय ढंग की दुर्घटना थी जहां पर रेल नदी में गिर गई थी और नदी से ऊपर एक सीढ़ी जैसी बन गई थी। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी जगह पर केन्द्रीय सरकार ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग क्यों नहीं मानती है। सरकार अनावश्यक ढंग से वांचू कमेटी की रपट का हवाला देती है और अगर वांचू कमेटी की रपट न रहे तो हमारी जिन्दगी न बचे। इस तरह की रपट तो कई लिखी जा सकती है।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है।

श्री राजनारायण : मेरा प्रश्न यह है कि जहां राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मूल्यांकन में अंतर हो, वहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी बिठलाने की मांग जो हमने बराबर की है उसके बारे में अंतिम फैसला क्या है। तो क्या जखनियां के बारे में ज्यडोशियल इन्क्वायरी बिठलाई जायेगी या नहीं बिठलाई जायेगी। अगर नहीं बिठलाई जायेगी तो क्यों नहीं बिठलाई जायेगी ?

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir. the question before the House was regarding the recommendation of the

Wanchoo Com nittee and that is why I referred to th; Wanchoo Committee. With respect to this particular accident I have no information just at present.

श्री राजनारायण : हमारी सूचना को मानकर क्या सरकार यहां पर जवाब देगी ।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार मदद नहीं दे रही है और आपने बिहार के संबंध में 8 केसेज बतलाये ।

श्री सभापति : मैंने आप से सवाल पूछने के लिए नहीं कहा बल्कि उनसे कहा है ।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बिहार में सारे देश के मुकाबले में एक तिहाई एक्सीडेंट हुए और जब बिहार केन्द्रीय सरकार के अधीन है, तो वह स्वयं कार्यवाही क्यों नहीं करती है ।

श्री मानसिंह वर्मा : माननीय मंत्री जी ने यात्रियों को संरक्षण देने में अपने मंत्रालय की असमर्थता प्रकट की है और इसका दायित्व राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया है । मैं उनसे स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि विगत 6 महीनों में राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या प्रयत्न किये और किस तरह से उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सका है ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : जैसा मैंने कहा कि वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वह राज्य सरकारों के पास भी जायगी और हमारी होम मिनिस्ट्री के पास भी है और उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं तथा मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं ।

TREATMENT OF RAILWAYMEN THROUGH INDIAN SYSTEN S OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY

*443. Si P. BHARGAVA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any representations have been received by Government from Railwaymen asking for facilities of treat-* ment through the Indian systems of - medicine and Homoeopathy;

(b) if so, whether it is proposed to recognise the Indian systems of medicine and Homoeopathy for treatment of the Railwaymen who show their preference for such treatment; and

(c) whether it is proposed to open Ayurvedic, Homoeopathic and Unani departments in Railway Hospitals throughout the country ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI P. GOVIND A MENON) : (a) The Railway Board have not received any such representation. The information whether zonal Railways have received any such representation is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as available.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

SHRI M. P. BHARGAVA : May I know whether the question has been • taken up with the Ministry of Health which has already recognised these systems and has also opened Ayurvedic and Unani dispensaries under the CGHS and may I also know whether the Railway Ministry also proposes to open Ayurvedic and Unani dispensaries in the Railway hospitals ?

SHRI P. GOVINDA MENON : In part (a) of the answer it has been stated that no representation has been received by the Railway Board. Therefore we did not make any further investigation in the matter. No railwayman has made any representation in this respect to the Railway Board. Information whether Zonal Railways have received such representations is being obtained from the Railways and will be placed on the Table of the House when available.

SHRI M. P. BHARGAVA : 1 would request the Minister to check up his facts again. May I know from him whether he is aware that the Health Ministry has recognised these systems and whether any consultation has tai place between the Railway Ministry . the Health Ministry on this question at all ?